7 मिलों के 5 तालाब और 18 कुएं जीवित , मगर अनदेखी से बने कूड़ा घर ..!

▶ यह कैसा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन....?

वीरेंद्र वर्मा

इंदौर। इंदौर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता का परिणाम है कि शहर में 7 कपड़ा मिले हुआ करती थी। सभी मिलों में पेड़ और पानी की विशेष व्यवस्था भी रही है। आज मिले भले ही बंद हो गई , लेकिन मिलों के अस्तित्व की निशानी के तौर पर आज भी शहर की 7 मिलों में से 5 मिलों में तालाब जिंदा है। वैसे हर मिल में एक तालाब और दो से चार कुएं है, लेकिन प्रशासन , नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और उदासीनता से शहर के लिए अमृत देने वाले जल स्त्रोत खत्म होने के कगार पर खड़े है।

इंदौर में करीब 20 हजार से ज्यादा मिल मजदूरों की प्यास बुझाने वाले कुएं और तालाब आज देश के सबसे स्वच्छ शहर में जीर्णोद्धार की राह देख रहे हैं। बताया जाता है कि किसी समय नगर निगम द्वारा शहर

में पानी की कमी होने पर टैंकर इन्हीं कुओं से भरते थे। सभी मिले में करीब 21 कुएं होते थे, मगर आज भी 18 कुएं जीवित और पानी से भरे पड़े है, जरूरत है तो सिर्फ इतनी कि कुओं की स्वच्छता या जल गंगा संवर्धन अभियान में सफाई और पानी को दूषित होने से रोकने की व्यवस्था हो जाए। आज भी पर्यावरण दृष्टि से मिलों में हजारों की संख्या में पेड़ खड़े है, जिनको विकास के नाम पर काटने की तैयारी हो रही है। आज पर्यावरण दिवस पर विशेष रूप से पेड़ लगाने, जल सहजने और बढ़ते तापमान पर चिंता जताई जाएगी। कई जगहों पर विचार गोष्ठी होगी और फोटो छप जाएंगे। क्या वास्तव में पर्यावरण संरक्षण को लेकर आम जनता, अधिकारी, जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं ? इसका जवाब आज शहर के दृष्टिकोण से नहीं है।

शहर के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की

उदासीनता का परिणाम है कि होप और कल्याण मिल के तालाब खत्म हो चुके है। दोनों मिल के तालाब अतिक्रमण और अन्य तरह के विकास की भेंट चढ़ गए। मगर अभी भी शहर के 7 मिलों के 18 कुएं जीवित है। यदि ईमानदारी से नगर निगम महापौर, अधिकारी और प्रशासन पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करना चाहते है, तो मिलों में मौजूद अमृत योजना में शहर का अमृत कुओं को संरक्षित करने का काम शुरू करें।

नहीं तो , पूर्व के तरह इंदौर शहर में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात सिर्फ विचार गोष्ठी तक सीमित होकर रह जाने वाली है। आज ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी से शहर का पर्यावरण संतुलन खत्म होने के कगार पर खड़ा है। इसको इस स्थिति में पहुंचाने का मुख्य कारण है कि सीमेंट कांक्रीट के जंगल बनाना, जिससे जमीन सूखती जा रही है और भू जल स्तर 800 फीट के करीब पहुंच गया है। देश के सबसे ज्यादा भू जल स्तर गिरने वाले शहर में इंदौर का नाम विकास में सीमेंट कांक्रीट के जंगल बनाने से जुड़ गया है। अधिकारी और जनप्रतिनिधि के गठबंधन ने शहर में तापमान बढ़ा दिया। आज पिछले 20 सालों में शहर के तापमान में 2 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है, जो आने वाले समय में 5 के स्तर पर पहुंच सकता है। शहर की कभी तासीर थी कि डग डग रोटी , पग पग नीर, मगर आज हालत गंभीर स्थिति में पहुंच गए है। ना नीर बचा है, ना ही शुद्ध हवा बची और ना पेड़ बचे है। यह कैसा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन है, कोई समझाए या बताएं ??

पानी की कमी अव्यवस्था का परिणाम - श्रमिक नेता धारीवाल

इंटक के हरनामसिंह धारीवाल कहते है कि शहर में पानी की कमी नहीं है, बल्कि पानी कमी अव्यवस्था का परिणाम है। अधिकारी और जनप्रतिनिधि में इच्छा शक्ति की कमी है। आज करोड़ों के विकास कार्य की बात होती है, लेकिन नगर निगम , आईडीए या अन्य सरकारी विभाग ने पानी के स्त्रोत बनाने का कार्य किया है क्या? आज झाड़ पेड़ों को काटने और सीमेंट कांक्रीट का जाल बिछाने से जो पानी जमीन में जाना चाहिए , वो पानी व्यर्थ नालों में बहकर जा रहा है। मिलों के कुएं ही संरक्षित कर दे , तो बहुत पानी की पूर्ति हो सकती है। सभी कुएं जीवित है।

शाजापुर की चीलर नदी..

जीवनदायिनी से नाला बनने का दर्द...

मनोज पुरोहित

शाजापुर. शाजापुर की पहचान रही चंद्रलेखा नदी, जिसे आज हम चीलर के नाम से जानते हैं, कभी शहर की जीवनदायिनी हुआ करती थी, लेकिन आज यह नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. विकास की अंधी दौड़ और प्रशासनिक लापरवाही के कारण यह पावन नदी अब एक बदबूदार बड़े नाले में तब्दील हो चुकी है. नदी की दुर्दशा का मुख्य कारण शहर के गंदे नालों का सीधा इसमें मिलना और जलकुंभी का बढ़ता साम्राज्य है. जलकुंभी ने नदी के जल प्रवाह को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है, जिससे पानी सडऩे लगा है. स्थिति यह है कि नदी के पास से गुजरना भी दूभर हो गया है. सबसे दुखद पहलू यह है कि हर साल चीलर नदी के उद्धार के लिए 32 करोड़ डीपीआर मध्य प्रदेश सरकार को भेजी है, ताकि चीलर नदी में मिलने वाले गंदे पानी को रोका जा सके . सौंदर्यीकरण के लिए जनभागीदारी और सरकार का सहयोग और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इसे जल्द पूरा करा जाएगा.

- भूपेंद्र कुमार दीक्षित, मुख्य नगर पालिका अधिकारी शाजापुर

शहर की जीवन दायिनी चीलर नदी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव मदद और आर्थिक सहयोग दिया जाएगा ताकि चीलर को फिर से चंद्रलेखा बनाया जा सकें .

- अरूण भीमावद विधायक शाजापुर

नदी सफाई अभियान के नाम पर लाखों रुपए का बजट आवंटित किया जाता है, लेकिन धरातल पर परिणाम शून्य ही रहते हैं.

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करोड़ों का जीर्णोद्धार

नगर पालिका ने नदी के घाटों के जीर्णोद्धार पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए, किंतु निर्माण कार्य में हुई धांधली आज भ्रष्टाचार की स्पष्ट गवाही दे रही है . घटिया सामग्री और लापरवाही के कारण ये घाट आज जर्जर हो चुके हैं . सच तो यह है कि नदी के नाम पर कई लोगों ने अपनी जेबें तो भरीं, लेकिन कोई भी इस नदी के प्रति ईमानदार नहीं रहा . यदि अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ी के लिए चीलर नदी केवल इतिहास के पन्नों में ही शेष रह जाएगी .

जनसहयोग, संरक्षण और जागरूकता से बदलेगी कुलबहरा नदी की तस्वीर

▶ कभी गर्मियों में भी कल-कल बहती थी नदी, अब संरक्षण की पहल की जरूरत

राजकुमार सोनी

छिंदवाड़ा / मोहखेड़. विश्व पर्यावरण दिवस केवल पौधारोपण का अवसर नहीं, बल्कि प्रकृति के उन अनमोल संसाधनों को बचाने का संकल्प लेने का दिन है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करते हैं। मोहखेड़ विकासखंड की जीवनदायिनी कुलबहरा नदी भी ऐसी ही प्राकृतिक धरोहर है, जिसने वर्षों तक क्षेत्र के किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों की प्यास बुझाई, लेकिन समय के साथ बदलते हालातों ने इसकी पहचान को प्रभावित किया है। एक समय था जब भीषण गर्मी के दिनों में भी कुलबहरा नदी में पानी लबालब रहता था। नदी के किनारों पर हरियाली नजर आती थी और ग्रामीणों का जीवन इससे जुड़ा हुआ था। लेकिन लगातार हुए अतिक्रमण, अनियंत्रित रेत खनन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण नदी का स्वरूप धीरे-धीरे सिकुड़ता चला गया। आज गर्मी के मौसम में नदी का अधिकांश हिस्सा सूना और वीरान दिखाई देता है। वर्षों से जल संरक्षण, नदी पुनर्जीवन और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर योजनाएं बनती रही हैं। हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस और अन्य अवसरों पर पौधारोपण, जल संरक्षण अभियान और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। सरकारी फाइलों और तस्वीरों में योजनाएं सफल दिखाई देती हैं, लेकिन कुलबहरा नदी की वर्तमान स्थिति इन दावों पर कई सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल संरक्षण के प्रयास धरातल पर प्रभावी ढंग से हुए होते तो आज कुलबहरा नदी गर्मी के दिनों में पूरी तरह सूखी नजर नहीं आती। नदी के अस्तित्व पर लगातार बढ़ते अतिक्रमण, अवैध रेत खनन और जल स्रोतों की अनदेखी का असर साफ दिखाई देता है। कई स्थानों पर नदी का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हुआ है, जिससे जल संग्रहण क्षमता भी कम हुई है।

जल संरक्षण के साथ हरियाली बढ़ाने की जरूरत

ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का संरक्षण और नदी किनारों पर हरित पट्टी विकसित करने जैसी पहलें नदी को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। देश के कई हिस्सों में जनसहयोग से सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने के सफल उदाहरण सामने आए हैं, जो कुलबहरा नदी के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं।

नदी बचेगी तो भविष्य बचेगा

कुलबहरा नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि क्षेत्र की संस्कृति, कृषि और जीवन का आधार है। विश्व पर्यावरण दिवस पर यह नदी हमें संदेश दे रही है कि पर्यावरण संरक्षण के दावे तभी सार्थक होंगे जब वे कागजों और तस्वीरों से निकलकर धरातल पर दिखाई दें। यदि आज कुलबहरा नदी को बचाने के लिए गंभीर प्रयास किए गए, तो आने वाली पीढ़ियां भी इसकी कल-कल बहती धारा और हरियाली का सुख प्राप्त कर सकेंगी।

इनका कहना है..

कुलबहरा नदी का घटता जलस्तर प्रकृति की चेतावनी है। नदी के जलग्रहण क्षेत्र में पौधारोपण, वर्षा जल संचयन और अतिक्रमण हटाने जैसे कदम उठाने होंगे। समाज और प्रशासन मिलकर काम करें तो नदी को फिर से जीवन मिल सकता है।

विलास घोंघे, सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता

कागजी योजनाओं से ज्यादा जरूरी जमीनी काम हैं। यदि नदी किनारे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण हो तो कुलबहरा नदी फिर से अपनी पुरानी पहचान हासिल कर सकती है। पर्यावरण दिवस पर यही सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए।

पंजाबराव डिगरसे,पर्यावरण जागरूक नागरिक

कटते पेड़ों के बीच हरियाली की नई इबारत

उज्जैन। एक ओर सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत शहर में सड़कों का जाल बिछ रहा है, नए ब्रिज, फ्लाईओवर, घाट और अधोसंरचनात्मक परियोजनाएं आकार ले रही हैं। इन विकास कार्यों के लिए हजारों पेड़ों की बलि भी दी जा रही है। दूसरी ओर प्रशासन, वन विभाग और नगर निगम कटते पेड़ों की भरपाई करने के उद्देश्य से 'ग्रीन सिंहस्थ' का प्रकल्प लेकर आया है।

उज्जैन में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान की तैयारी की गई है ।पंचकोशी मार्ग, मेला क्षेत्र, नई सड़कों के किनारे और शिप्रा घाटों के आसपास हरित कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। अमलतास, गुलमोहर, पलाश, नीम और कदम जैसे छायादार एवं फूलदार पौधों का चयन किया गया है ताकि सिंहस्थ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और संतों को प्राकृतिक छांव मिल सके।

ग्रीन कुंभ का कांसेप्ट

प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ-2028 को देश का पहला 'ग्रीन कुंभ' बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत लाखों पौधे लगाने, वन क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की योजना पर काम चल रहा है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर भी शहर में व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा।

चुनौती भी बहुत

विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की यह चुनौती आने वाले वर्षों में उज्जैन के भविष्य की दिशा तय करेगी। सवाल यह है कि क्या कटते पेड़ों की भरपाई नई हरियाली कर पाएगी? क्योंकि इन पौधों को सहेजना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है।

वृक्ष मित्र करेंगे तैयार

नवभारत से चर्चा में उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि सिंहस्थ-2028 को न सिर्फ ग्रीन सिंहस्थ के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है बल्कि पंचकोशी मार्ग और मेला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने के साथ छायादार लाखों पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए 'वृक्षमित्र' तैनात किए जा रहे हैं।

नाले में तब्दील हो गई बोदरी नदी, शहर का गंदा पानी मुख्य कारण

समाप्त होते जा रहा बोदरी नदी का अस्तित्व

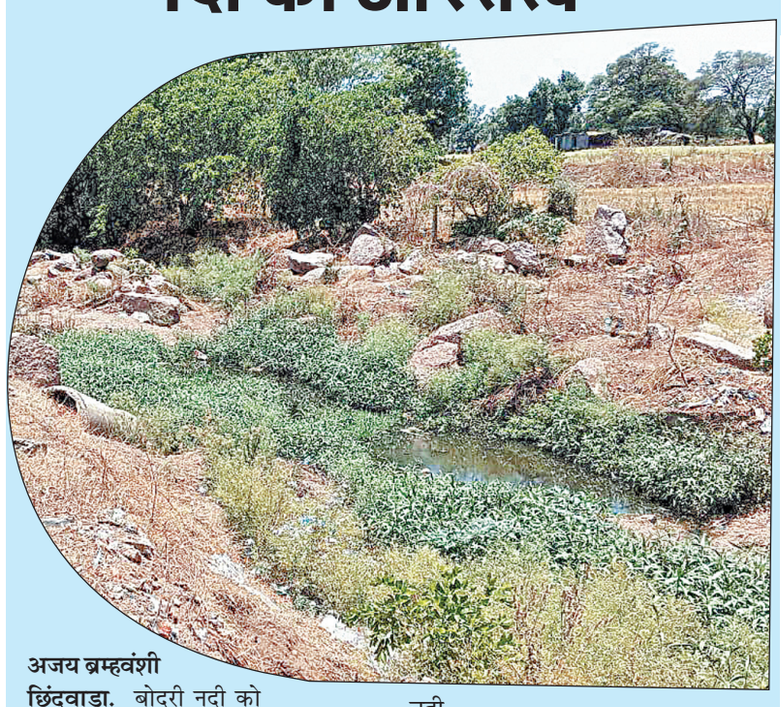

अजय ब्रम्हवंशी

छिंदवाड़ा. बोदरी नदी को अब लोग बोदरी नाला कह कर संबोधित करने लगे है. इसका सबसे बड़ा कारण नदी के आस पास अतिक्रमण, सीवरेज की पाईप लाइन और शहर से निकले वाला गंदा पानी है. शहर के बीचों बीच बहने वाली बोदरी नदी में 15 वर्ष पूर्व साल भर कंचन सा पानी बहता था लेकिन अब यह नदी का अस्तित्व समाप्त होते जा रहा है. बता दे कि कभी बोदरी नदी शहर की जीवन रेखा हुआ करती थी बोदरी नदी का नाम सरकारी कागजों में ही है और निगम व प्रशासन की लापरवाही से यह एक नाला बन चुकी है. ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि इस नदी के उद्धार के लिए भगीरथ कौन बनेगा. बोदरी नदी में पहले लोग गणेश विर्सजन , दुर्गा विसर्जन करने जाते थे, साथ ही लोग इस नदी में तैराकी का भी लुफ्त उठाते थे, सावन के महिने में तीज के त्योहार पर महिलाएं तीज विर्सजन करने के लिए जाया करती थी. वह पुरानी दिन याद आने पर वे दिन सपना सा दिखाई देते है.

नदी में गड़ाई गई सीवरेज पाइप लाईन

बता दे कि शहर का गंदा पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए प्रशासन ने शहर में सीवरेज की पाइप लाइन बिछाया है. शहर में बिछाए गए पाईप लाइन को बोदरी नदी में बिछाए गए पाइप लाईन से जोड़ दिया गया. बोदरी नदी के नाले में तब्दील होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि बोदरी नदी में सीवरेज कम्पनी ने गढड़ा खोद कर पाईप लाइन बिछा दिया है नदी में खुदाई करने से यह हालत उत्पन्न हुए है.

प्रदूषित हो गई बोदरी नदी

शहर का सारा कूड़ा-निस्तारण दोनों नदियों के मुहाने पर ही झोंका जाता है. इससे नदी का जल तो प्रदूषित होता ही है साथ ही आसपास का वातावरण भी दूषित हो गया है. नदी में आवारा मृत पशु, लावारिस लाशें, पॉलीथिन में बंधा कूड़ा ढेर ने नदियों के जल को विषैला बना दिया है. शासन-प्रशासन प्रयास करने पर भी अब तक टंड्क्षचग ग्राउंड की तलाश नहीं कर सका. शहर में अब तक सीवर लाइन सिस्टम को दुरस्त न करने से नालों का पानी नदियों में गिरने से नदियों की बेवजह मौत हो रही है. जिसके लिए काफी हद तक दोषी शासन भी है.

इनका कहना है...

बोदरी नदी का वजूद खतरे में है. नदी आबादी बढऩे से नदी संकीर्ण हो गई है. नदी को पुर्नजीवित करने के लिए शहरवासियों को आवाज उठाना होगा और शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना होगा तब कही जाकर बोरदी नदी का हम अस्तित्व बचा पाएगे.

तोलेश मंडराह
पर्यावरण प्रेमी छिंदवाड़ा

अस्तित्व के लिए जूझ रही जीवनदायिनी कन्हान ; राजस्व बटोरने में व्यस्त सरकार के पास संरक्षण का कोई प्लान नहीं

पुरुषोत्तम पोतरे

सौंसर . एक तरफ जहां आज पूरा विश्व विश्व पर्यावरण दिवस मनाकर धरती और प्रकृति को बचाने का संकल्प ले रहा है, वहीं दूसरी ओर सौंसर क्षेत्र की एकमात्र जीवनदायिनी कन्हान नदी तिनके-तिनके की तरह अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। विडंबना यह है कि प्रदेश सरकार इस नदी से हर साल करोड़ों रुपये का राजस्व तो बटोरती है, लेकिन इसके संरक्षण और बचाव के लिए सरकारी फाइलों में कोई ठोस योजना नजर नहीं आती।

इनका कहना है..

क्षेत्रीय नदियों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रदेश सरकार को तत्काल और उचित कदम उठाने चाहिए। यदि समय रहते कड़े फैसले नहीं लिए गए, तो पर्यावरण का असंतुलन इस कदर बढ़ जाएगा कि हमारी जीवनदायिनी नदियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। **गोपाल कोठे पर्यावरण प्रेमी सौंसर**

बेतरतीब और अत्यधिक रेत उत्खनन ने नदी के भूगोल को बिगाड़ कर रख दिया है। कटाव को रोकने के लिए कोई पुख्ता कदम न उठाए जाने के कारण नदी का प्राकृतिक स्वरूप लगातार सिमट रहा है। इसका सीधा असर क्षेत्र के जलस्तर पर पड़ा है, जो काफी नीचे खिसक चुका है। जो कन्हान नदी का कभी भीषण गर्मी के सीजन में भी कलकल बहा करती थी, आज उसकी धारा कुछ हिस्सों में सिमटकर महज एक नाले जैसी दिखने लगी है। इसके विपरीत, बारिश के दिनों में यही अनियंत्रित नदी तटीय क्षेत्र के किसानों के खेतों में तबाही मचाती है।

सरकार की कमाई का बड़ा जरिया, पर सुध लेने वाला कोई नहीं

कन्हान नदी का दायरा सौंसर के बारादेवी से लेकर महाराष्ट्र की सीमा से लगे ग्राम मालेगांव तक फैला हुआ है। आबकारी के बाद सरकार को सबसे बड़ी आय इसी क्षेत्र की घोषित रेत खदानों से मिलती है। यहां की उच्च गुणवत्ता वाली रेत की मांग पूरे महाराष्ट्र विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में है। सरकार खदानें नीलाम कर करोड़ों की कमाई तो कर रही है, लेकिन पर्यावरण संतुलन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है।

नागपुर और औद्योगिक क्षेत्र की प्यास बुझाती है कन्हान

कन्हान नदी सिर्फ सौंसर ही नहीं, बल्कि अंतरराज्यीय स्तर पर जीवन का आधार है। बोरगांव-खैरीतायगांव में स्थित औद्योगिक ग्रोथ सेंटर पूरी तरह कन्हान के पानी पर निर्भर है ।यही नही मध्य भारत के सबसे बड़े महानगर नागपुर को भी कन्हान नदी से ही पेयजल की आपूर्ति होती है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने सीमा पर कोच्छी बांध का निर्माण भी किया है। बहरहाल ?यदि नदी का जलस्तर इसी तरह गिरता रहा, तो आने वाले समय में एक बड़ा जल संकट खड़ा होना तय है, जिसका खामियाजा किसानों, आम जनता और उद्योगों तीनों को भुगतना पड़ेगा।

कागजी साबित हो रहे सामाजिक संगठनों के दावे

वर्तमान में कन्हान नदी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है। बढ़ते कटाव और अत्यधिक दोहन से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है। दुखद पहलू यह भी है कि सरकारी उदासीनता के बीच सामाजिक संगठनों द्वारा किया जाने वाला शोर-शराबा भी महज %विश्व पर्यावरण दिवस% जैसे मौकों पर फोटो खिंचवाने और खानापूर्ति करने तक ही सिमट कर रह गया है। धरातल पर कोई ठोस काम नजर नहीं आता।

हिरन नदी का संकट में अस्तित्व

आदित्य सिंह

सीधी। अतिक्रमण का दंश झेल रही हिरन नदी का अस्तित्व संकट में है। सरकार के जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होने के बाद भी हिरन नदी का उद्धार नहीं हुआ।

शहर की प्राचीनतम हिरन नदी अस्सी के दशक तक जल से समृद्ध बड़ी नदी थी। उस दौरान तक बाजार क्षेत्र के लोगों के स्नान एवं पीने के पानी की जरूरतें भी यहां से पूरी होती थी। नल से पानी सप्लाई की व्यवस्था बढ़ने के बाद हिरन नदी पर लोगों की निर्भरता कम होती गई। नतीजन कुछ लोगों द्वारा हिरन नदी के किनारे खाली पड़े विशाल भू- क्षेत्र पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया गया। दो हजार के दशक के बाद तो हिरन नदी को पाटकर अवैध कब्जा करने की होड़ मची गई। भारी अतिक्रमण के चलते शहर के थनहवा टोला से लेकर चकदही पुल तक हिरन नदी का बजूद नाला और नाली के रूप में नजर आने लगा। हिरन नदी के बजूद को बचाने शहरवासी अर्से से जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लिहाजा शहरवासियों की मांग पर जनप्रतिनिधियों की पहल के बाद कलेक्टर एवं एसडीएम गोपद बनास के निर्देशानुसार तहसीलदार के आदेश पर हिरन नदी के सीमांकन की कार्यवाई पिछले वर्ष हो चुकी है। सीमांकन में कोतरकला एवं कोटहा क्षेत्र की नदी के लिये अलग-अलग राजस्व टीम गठित की गयी थी। कोतरकला में 21 अतिक्रमणकारी चिन्हित किये गये हैं वहीं कोटहा क्षेत्र में दर्जन भर अतिक्रमणकारी चिन्हित किये गये। दोनो टीमों के राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन एवं चिन्हित अतिक्रमणों का प्रतिवेदन तहसीलदार गोपदबनास को पिछले वर्ष ही सौंपा जा चुका है। नगर पालिका परिषद सीधी की ओर से पहले वर्ष अतिक्रमण हटाने की नोटिस भी पिछले साल संबंधितो को देकर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने 7 दिवस का समय दिया गया था। समय व्यतीत होने के बाद कार्रवाई की बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

नदी से नाली में परिवर्तित हुई हिरन नदी -हिरन नदी में भारी अतिक्रमण के चलते इसका स्वरूप अधिकांश स्थानों में नाली में परिवर्तित हो चुका है। शहर की प्रमुख हिरन नदी के सीमांकन के बाद चिन्हित अतिक्रमण हटने का इंतजार लंबा हो चुका है। नदी से नाला बनी हिरन नदी को अतिक्रमण से मुक्त कराने एक वर्ष के प्रयास के बाद हुये सीमांकन में चिन्हित अतिक्रमणकारियों को हटाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है।

उज्जैन में एक गंदे नाले को साफ करने की कीमत 10 करोड़

प्रमोद व्यास

उज्जैन । क्षिप्रा नदी को प्रदूषित होने से बचाने और कान्ह नदी का गंदा पानी इसमें मिलने से रोकने के लिए 919 करोड़ का क्लोज्ड-डक्ट डायवर्जन प्रोजेक्ट बनाया गया है। शहर के 10 से 12 बड़े गंदे नाले क्षिप्रा में समाहित हो रहे हैं,कुल मिलाकर देखें तो इन्हें रोकने के तहत एक नाले पर ही 10 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो रहा है।

इस प्रोजेक्ट के तहत इंदौर की तरफ से आने वाली कान्ह नदी के प्रदूषित पानी को उज्जैन के गोठड़ा गांव के पास रोक लिया जाएगा। इसके लिए 30 किलोमीटर लंबी नहर और टनल प्रणाली बनाई जा रही है, जो गंदे पानी को सीधे शिप्रा नदी के घाटों (जैसे रामघाट, त्रिवेणी और सिद्धवट) से दूर ले जाएगी।

शहर के स्थानीय नाले-शनि मंदिर से लेकर सिद्धवट तक नदी के किनारों पर से 10 से 12 नाले चिह्नित किए गए है, इसमें ऋणमुक्तेश्वर और जूना सोमवारिया क्षेत्र के नाले सीधे नदी में गिरते हैं ?कान्ह नदी इंदौर का औद्योगिक और घरेलू कचरा कान्ह नदी के माध्यम से शिप्रा में मिलता है ।

काला रंग नदी दूषित कर रहा -चक्रतीर्थ, मंगलनाथ, और भैरवगढ़ (बटिक प्रिंटों का केमिकल युक्त पानी) के पास स्थित आश्रमों, कॉलोनियों और होटलों का गंदा काला पानी भी बिना ट्रीटमेंट के नदी में जा रहा है,नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, धरातल पर अभी भी कई अनट्रीटेड नाले सीधे शिप्रा में मिल रहे हैं

करोड़ों खर्च नतीजा सिफर

सिंहस्थ 2016 के लिए नर्मदा-शिप्रा संगम प्रोजेक्ट पर 432 करोड़, एवं 438 करोड़ के सीवरेज प्लान में भी नदी के पास लाइन डालने पर खर्च किया । यानी शिप्रा के पानी को साफ करने जितने भी काम हुए, वे प्लान फ्लॉप साबित हुए।

यहां मिल रहे नाले

मंगलनाथ के पीछे अंगारेश्वर के पास, वाल्मीकि धाम, सोमकुंड, दानी गेट, वाकणकर ब्रिज, त्रिवेणी, हाटकेश्वर कॉलोनी, काला पत्थर, त्रिवेणी इंदौर रोड पुलिया के नीचे नालों का गंदा पानी सीधे नदी में मिल रहा है। त्रिवेणी पर ही कान्ह का गंदा पानी भी शिप्रा में आ रहा है।